

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा-श्रमिक भी ले सकेंगे
निःशुल्क राशन का लाभ

नवीन हितग्राहियों के दस्तावेजों का करें तुरंत सत्यापन: कलेक्टर

बैतूल: कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवर्षी ने जिले के जनपद पंचायत तथा नगरीय निकाय को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने वाले असंगठित अप्रवासी श्रमिकों के दस्तावेजों का सत्यापन शीघ्र किया जाए, जिससे उन्हें ऐसे राशन मित्र पोर्टल पर जोड़ा जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 20वाँ श्रेणी के रूप में असंगठित एवं अप्रवासी श्रमिक वर्ग को जोड़ा गया है।

राशन मित्र पोर्टल पर पंजीयन

राशन मित्र पोर्टल पर पाप्रता पर्ची के लिए आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है। समग्र सामाजिक सुधार मिशन पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत सम्पर्क अईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी होना आवश्यक है। आवेदक एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की खाद्य प्रति, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का ई-कार्ड, केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का यूएन नंबर अथवा ई-कार्ड की प्रति परिवार के सभी कीपों एवं सदस्यों का मानविक नंबर होना आवश्यक है। असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों के अंतर्गत ऐसे श्रमिक जो श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना एवं केन्द्र सरकार के कार्ड ई-श्रम में पंजीकृत होना चाहिए। संबल योजना एवं ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे प्रवासी श्रमिकों जो ना तो शासकीय सेवा में हो और न ही आयकरक श्रमिकों की श्रेणी में होना चाहिए। उद्देश्य इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क राशन प्राप्त करने के लिए चिन्हित 27 श्रेणियों को राशन वितरित किया जा रहा है। आदेशनुसार अब असंगठित एवं अप्रवासी श्रमिक वर्ग को सूची में 28 वीं श्रेणी के रूप में जोड़ा गया है।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए संबल एवं ई-श्रमिक योजना में पंजीकृत श्रमिकों से पाप्रता पर्ची के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय-सीमा में आवेदन प्राप्त कर ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य शासन के साथ संवाद बढ़ावा देता है और नगर पालिका कार्यालय की महावाक्यक्रमी इस योजना का लाभ हितग्राहियों को शत-प्रतिशत मिल सके, इसके लिए प्रत्येक हितग्राही को झोला जाएगा।

आज भी नेटवर्क विहीन हैं बैतूल जिले के 200 गांव

बैतूल: 21वीं सदी के भारत में, जहां टेक्नोलॉजी और संचार सेवाओं का विकास तेजी से हो रहा है, वहीं बैतूल जिले के लागड़ा 200 गांव अब भी नेटवर्क से वंचित हैं। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव ने संचार मंत्री श्रीमत ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकूत कर इन गांवों को बी-एस-एन-एल नेटवर्क से जोड़ने की मांग की है।

दिनेश यादव ने संचार मंत्री को बताया कि बैतूल जिला प्राकृतिक सुंदरता से बिहारी हुआ है, जहां पहाड़ों और पर्वत छेंगलाओं के बीच छोट-छोटे गांव बसे हैं। इन गांवों में मुख्य रूप से आदिवासी समाज निवास करता है, जो संबल सेवाओं की कमी का सामना कर रहा है। नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीणों को सकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही जननी एक्सप्रेस जैवी सुविधाएं भी इन गांवों तक नहीं पहुंच पातीं, जिससे प्रसव के समय महिलाओं को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो कई बार जननेवा साक्षित होता है। 21वीं सदी के भारत का प्रगति के लिए ग्रामीण युवाओं और छात्रों का टेक्नोलॉजी से जुड़ना आवश्यक है। नेटवर्क की कमी के कारण यहां के युवा और छात्र शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

संचार मंत्री ने दिया आधारन

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिनेश यादव को आशासन दिया कि बैतूल जिले के नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों में जल्द ही टाकर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। बी-एस-एन-एल की 4जी सेवाएं इन गांवों तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे प्रसव के समय महिलाओं को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो कई बार जननेवा साक्षित होता है। 21वीं सदी के भारत का प्रगति के लिए ग्रामीण युवाओं और छात्रों का टेक्नोलॉजी से जुड़ना आवश्यक है। नेटवर्क की कमी के कारण यहां के युवा और छात्र शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

हाईटेक लाइब्रेरी में बढ़ रहे हैं विद्यार्थी और घट रही है सुविधा

विधायक बोले : उठाएंगे कदम,
बेहतर होगी व्यवस्थाएं

बैतूल/मुलताई: मुलताई की एकमात्र हाईटेक लाइब्रेरी में कॉम्प्यूटर्स एवं एक्साम की तैयारी करने वाली समस्याओं की संरचना बढ़ती जा रही है और अब इसके साथ ही लाइब्रेरी में सुविधाओं का अभाव भी बढ़ता जा रहा है। इस लाइब्रेरी में नियमित अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राएं लेबोर समय-सीमा में इंटरनेट डाटा, सीटिंग व्यवस्था, फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाओं बढ़ने की मांग करते आ रहे हैं किंतु कोई नीतीजा नहीं निकलता। आज इंद्रांगनी गांवी बाड़ में स्थित हाईटेक लाइब्रेरी में पढ़ने आने

वाले छात्र छात्राओं ने यहां होने वाली समस्याओं के लिए मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख से भाजपा कार्यालय में भूलकात की। उन्होंने बताया कि यहां पर आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त फर्नीचर नहीं होने की वजह से वे यहां अध्ययन नहीं कर पाए हैं। वहां पर्याप्त मात्र में किटाबों और इंटरनेट कोनेशन नहीं होने की वजह से भी अध्ययन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने विधायक से इस दिशा में जल्द ही आवश्यक करार उठाएंगे। फिलहाल उन्होंने नगर पालिका सीएमएसी से चर्चा कर व्यवस्था बनाने के लिए कहा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा-श्रमिक भी ले सकेंगे निःशुल्क राशन का लाभ नवीन हितग्राहियों के दस्तावेजों का करें तुरंत सत्यापन: कलेक्टर

बैतूल: कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवर्षी ने जिले के जनपद पंचायत तथा नगरीय निकाय को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने वाले असंगठित अप्रवासी श्रमिकों के दस्तावेजों का सत्यापन शीघ्र किया जाए, जिससे उन्हें ऐसे राशन मित्र पोर्टल पर जोड़ा जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 20वीं श्रेणी के रूप में असंगठित एवं अप्रवासी श्रमिक वर्ग को जोड़ा गया है।

राशन मित्र पोर्टल पर पंजीयन

राशन मित्र पोर्टल पर पाप्रता पर्ची के लिए आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है। समग्र सामाजिक सुधार मिशन पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत सम्पर्क अईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी होना आवश्यक है। आवेदक एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की खाद्य प्रति, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का ई-कार्ड, केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का यूएन नंबर अथवा ई-प्रमाण पर्ची के अंतर्गत एवं अप्रवासी श्रमिक वर्ग को जोड़ा गया है।

राशन मित्र पोर्टल पर पंजीयन

राशन मित्र पोर्टल पर पाप्रता पर्ची के लिए आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है। समग्र सामाजिक सुधार मिशन पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत सम्पर्क अईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी होना आवश्यक है। आवेदक एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की खाद्य प्रति, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का ई-कार्ड, केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का यूएन नंबर अथवा ई-प्रमाण पर्ची के अंतर्गत एवं अप्रवासी श्रमिक वर्ग को जोड़ा गया है।

राशन मित्र पोर्टल पर पंजीयन

राशन मित्र पोर्टल पर पाप्रता पर्ची के लिए आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है। समग्र सामाजिक सुधार मिशन पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत सम्पर्क अईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी होना आवश्यक है। आवेदक एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की खाद्य प्रति, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का ई-कार्ड, केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का यूएन नंबर अथवा ई-प्रमाण पर्ची के अंतर्गत एवं अप्रवासी श्रमिक वर्ग को जोड़ा गया है।

राशन मित्र पोर्टल पर पंजीयन

राशन मित्र पोर्टल पर पाप्रता पर्ची के लिए आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है। समग्र सामाजिक सुधार मिशन पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत सम्पर्क अईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी होना आवश्यक है। आवेदक एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की खाद्य प्रति, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का ई-कार्ड, केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का यूएन नंबर अथवा ई-प्रमाण पर्ची के अंतर्गत एवं अप्रवासी श्रमिक वर्ग को जोड़ा गया है।

राशन मित्र पोर्टल पर पंजीयन

याइट विलक



अजय बोकिल

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नया अंतर्राजातीय संघर्ष शुरू होगा

दे | श में एससी/एसटी (अनुसूचित जाति/जनजाति) वर्ग में भी उप श्रेणी यानी कटोरे में कोटा को मंजूरी और इन दोनों आरक्षित श्रेणियों में भी ओवीसी की तर्ज पर क्रीमी लेयर तय करने के सुप्रीम को 6:1 के बहुमत से दिए फैसले के दूरामी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है, लेकिन ज्यादातर हल्कों में इस फैसले का स्वातंत्र्य हुआ है, क्योंकि देश में अरक्षण की जो कहानी 1882 में विलियम हंडर और ज्योतिन फुले ने शुरू की थी, करीब डेढ़ सौ साल बाद इसमें नया और नियायिक मोड़ आ गया है।

एक बार के बाद 70 सालों से साकारी नैकरियों और शिक्षण संस्थानों में अरक्षण की भीतर से आवाज उठने लगी थी कि अरक्षण का फायदा भी समान रूप से सभी जातियों को नवीनी मिल रहा है। लिहाजा इस लाभ का वितरण नए और न्यायसंगत तरीके किया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो अरक्षण का लाभ उठाकर आर्थिक व सामाजिक बेहतरी हासिल करने वाला एक नए किस्म का 'ब्राट्स्पन्डाव' इन जाति वर्गों में भी आकर लेने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामाजिक न्याय के लिए एक उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। क्योंकि आरक्षित वर्ग के भीतर ही हिंदू देखा जाना चाहिए।

इसके लिए वर्ग के अन्दर उन्हें किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण के बाहर राज्य अपने यहां अरक्षित श्रेणियों में अधिक लाभान्वित और कम लाभान्वित जातियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। हालांकि यह काम बहुत साधारणी और पारदर्शिता से करना होगा। इसके लिए सही अंकड़े जुटाने होंगे। केवल वोटों की गोलबद्दी के बजाए आरक्षण के समान वितरण की अनुसूचित क्रिया अपनी होगी।

इसके लिए वर्ग का विरोधी यह कमजोर तर्क जरूर देते हैं कि पैसे और मान्यता के विरोधी यह कमजोर तर्क जरूर देते हैं कि पैसे और समाजिक प्रतिष्ठा और समानता नहीं मिलती, जिसकी कि दलित और अदिवासियों को पढ़ती दरकार है। मन से सामाजिक समाज को स्वीकार करना और उपका आदर करना एक लंबी और दीर्घकालीन प्रक्रिया का हिस्सा है। जो जातिवाद की जो ब्राईं सैकड़ों सालों में हिंदू समाज में गर्हे तक घर कर गई है, उसका उच्चाटन होने में समय लगेगा। उसके लिए कानून के साथ-साथ मानसिकता बदलने की जरूरत है धीरे-धीरे वह बदल भी रही है। लेकिन एक जातिवादी ने ज्यादा उठाया है, जैसे कि जाटव, महार, मेहरा और अहिंसार आदि। लेकिन उन्होंने की एक हजार से अरक्षित बंधु जातियों इस मामले में बहुत पीछे छूट गई हैं। अगर इस श्रेणी में सब कोटा होगा तो अरक्षण सुविधा का लाभ ज्यादा बेहतर और न्यायसंगत तरीके से वितरित हो सकता है। यदि बात अनुसूचित जनजाति (आवादी) का लिए भी लागू होती है, तब वही 744 जनजातियों हैं, लेकिन रिजेशन का लाभ मुख्य रूप से गोड़, भील, सथल आदि अदिवासियों ने ही उठाया है। इसका एक प्रमुख कारण यहां और जामानकता का अधाव भी है। काफी कुछ यही स्थिति अति पिछड़ा वर्ष में भी है, जहां 5013 जातियां हैं, लेकिन उन्हें प्रदत्त 27 फीसदी आरक्षण से लाभान्वित होने वाली प्रमुख जातियां यादव, कुण्डी, कुमी, कलार, सोनी आदि ही हैं। हालांकि ओवीसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्रांति के लिए भी शामिल है। जिसके मुताबिक वर्तमान में क्रांती लेयर की शर्त लगा रखी है। अगर इसका लिए वर्ग का विवादित वर्ग के भीतर ही होती है, तो अरक्षण के लाभ की ही होती है। अगर दलित या अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ों को श्रेणियों में बांटकर उन्हें अरक्षण के लाभ देने की कोशिशें कुछ राज्यों ने पहले से शुरू कर दी थीं। लेकिन इसे सामाजिक न्याय के बजाए वोटों की गोलबद्दी की पुनर्वचना के प्रयत्न के रूप में ज्यादा देखा गया। खासकर नीतीश कुमार ने बिहार में इसकी पहल तेजी की थी।

दुर्भाग्य से यह सच्चाई है कि आप किसी को कितना भी आरक्षण दें, लेकिन उसके बास्तविक लाभार्थी कुछ लोग अथवा जातियों ही होती है। अगर दलित या अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ों को श्रेणियों में बांटकर उन्हें अरक्षण के लाभ देने की कोशिशें कुछ राज्यों ने पहले से शुरू कर दी थीं। लेकिन इसे सामाजिक न्याय के बजाए वोटों की गोलबद्दी की पुनर्वचना के प्रयत्न के रूप में ज्यादा देखा गया। खासकर नीतीश कुमार ने बिहार में बिहार में ज्यादा देखा गया है। आरक्षण की सुविधा 'जन्मसिद्ध अधिकार' में बदलने लगी है। हालांकि इस

सामाजिक आर्थिक परिस्थिति व चेतना अलग-अलग है। यही कि जिन आरक्षित जातियों में अपने हिंदू और स्वामियान को लेकर ज्यादा चेतना है, वो आरक्षण का लाभ उतना ही ज्यादा उठा पाते हैं। मोटे पर एससी श्रेणी में अरक्षणतण का फायदा करीब एक दर्जन जातियों ने ज्यादा उठाया है, जैसे कि जाटव, महार, मेहरा और अहिंसार आदि। लेकिन उन्होंने की एक हजार से अरक्षित बंधु जातियों इस मामले में बहुत पीछे छूट गई हैं। अगर इस श्रेणी में सब कोटा होगा तो अरक्षण सुविधा का लाभ ज्यादा बेहतर और न्यायसंगत तरीके से वितरित हो सकता है। यदि बात अनुसूचित जनजाति (आवादी) का लिए भी लागू होती है, तब वही 744 जनजातियों हैं, लेकिन रिजेशन का लाभ मुख्य रूप से गोड़, भील, सथल आदि अदिवासियों ने ही उठाया है। इसका एक प्रमुख कारण यहां और जामानकता का अधाव भी है। काफी कुछ यही स्थिति अति पिछड़ा वर्ष में भी है, जहां 5013 जातियां हैं, लेकिन उन्हें प्रदत्त 27 फीसदी आरक्षण से लाभान्वित होने वाली प्रमुख जातियों यादव, कुण्डी, कुमी, कलार, सोनी आदि ही हैं। हालांकि ओवीसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्रांति के लिए भी लागू होती है। लेकिन उन्हें अन्य जातियों में अवसरों की लाभान्वित करने के लिए लड़ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा जातियों में ज्यादा जातियों में अवसरों की लाभान्वित करने के लिए लड़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में जिन चार जोड़ों ने ऋषि विलायत के विवरण कैसे हो, इसका राजनीतिक रूप से प्रयास तो पहले से ही शुरू हो गए थे। मसलन दर्शन के में अति दलित अथवा मानसिक, पिछड़ों में अति पिछड़ों को श्रेणियों में बांटकर उन्हें अरक्षण के लाभ देने की कोशिशें कुछ राज्यों ने पहले से शुरू कर दी थीं। लेकिन इसे सामाजिक न्याय के बजाए वोटों की गोलबद्दी की पुनर्वचना के प्रयत्न के रूप में ज्यादा देखा गया। खासकर नीतीश कुमार ने बिहार में बिहार में वैसा होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रांति के लिए वाली जातियों में एक नया संघर्ष शुरू होने की सभावना है, जो आरक्षित वर्गों में एक नया समाज बनाने की चाहीदा जातियों यादव, कुण्डी, कुमी, कलार, सोनी आदि ही है। हालांकि ओवीसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्रांति के लिए ज्यादा डाटा इकट्ठा करना होगा। हो सकता है कि सरकार आगे सालों ताल होने वाली जायगाना में इसे भी शामिल करना चाहिए। लेकिन उसके भी पहले नई राजनीतिक गोलबद्दियां तेज होंगी। एससी/एसटी में अरक्षण का ज्यादा लाभ उठाने वाली जातियों इसके समर्थन में जुटींगी। यानी आरक्षित वर्गों में एक नया संघर्ष शुरू होने की सभावना है, जो सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता की कोख से ही पैदा होगा। जाहिर है कि राजनीतिक आवादी अपने ढांचे से अलग उठायेंगे। इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधायक सभा चाहीदों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि सरकार इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण की अनीति विवरण के बावजूद लोगों के लिए वाली जातियों इसके समर्थन में जुटींगी। यानी आरक्षित वर्गों में एक नया संघर्ष शुरू होने की सभावना है, जो सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता की कोख से ही पैदा होगा। जाहिर है कि राजनीतिक आवादी अपने ढांचे से अलग उठायेंगे। इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधायक सभा चाहीदों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि सरकार इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण की अनीति विवरण के बावजूद लोगों के लिए वाली जातियों इसके समर्थन में जुटींगी। यानी आरक्षित वर्गों में एक नया संघर्ष शुरू होने की सभावना है, जो सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता की कोख से ही पैदा होगा। जाहिर है कि राजनीतिक आवादी अपने ढांचे से अलग उठायेंगे। इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधायक सभा चाहीदों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि सरकार इस फैसले पर कहा कि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण की अनीति विवरण के बावजूद लोगों के लिए वाली जातियों इसके समर्थन में जुटींगी। यानी आरक्षित वर्गों में एक नया संघर्ष शुरू होने की सभावना है, जो सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता की कोख से ही पैदा होगा। जाहिर है कि राजनीतिक आवादी अपने ढांचे से अलग उठायेंगे। इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधायक सभा चाहीदों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि सरकार इस फैसले पर कहा कि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण की अनीति विवरण के बावजूद लोगों के लिए वाली जातियों इसके समर्थन में जुटींगी। यानी आरक्षित वर्गों में एक नया संघर्ष शुरू होने की सभावना है, जो सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता की कोख से ही पैदा होगा। जाहिर है कि